# फ्यूल चार्ज के नाम पर कट रही बिजली उपभोक्ताओं की जेब

## प्रदेश में अगले महीने से बढ़ेगा बिजली का बिल

- उपभोक्ता को अब नवम्बर और दिसम्बर में जारी होने वाली बिल में 21 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी
- हालांकि कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज राशि का प्रभाव नहीं पड़ेगा

**जयपुर**, (का.सं.)। प्रदेश में फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं की जेब काटी जा रही है। उपभोक्ता को अब नवम्बर और दिसम्बर में जारी होने वाली बिल में 21 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी। डिस्कॉम्स प्रशासन ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज की राशि को सरकार अनुदान के रूप में वहन कर रही है।

डिस्कॉम्स अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत ने बताया कि डिस्कॉम विद्युत आपूर्ति हेतु विभिन्न स्त्रोतों से राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्थायी एवं परिवर्तनीय दर से बिजली क्रय करता है। विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियम-2019 के प्रावधान के अनुसार विद्युत खरीद की अनुमोदित परिवर्तित दर एवं विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर का अन्तर फ्यूल सरचार्ज के रूप में त्रैमासिक आधार पर विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करने का प्रावधान है। विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर अधिक होने का मुख्य कारण कोयले की दरों में वृद्धि, मालभाड़े में वृद्धि एवं विभिन्न करों में बदलाव है।

सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 के लिए माननीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित गणना प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली योग्य फ्यूल सरचार्ज की राशि 21 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। यह राशि पिछली तिमाही जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 के उपभोग पर वसूलनीय है।

उन्होंने बताया कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं पर आने वाले भार को देखते हुये राहत देने के उद्देश्य से इस फ्यूल सरचार्ज राशि को दो समान किश्तों में माह नवम्बर व दिसम्बर, 2022 के बिजली बिलों के माध्यम से वसूल किया जाना प्रस्तावित है। कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज की राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाता है।

सावंत ने बताया कि विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार फ्यूल सरचार्ज की गणना को स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा वेरिफिकेशन के पश्चात् ही लागू किया जाता है।

## ईटीपी लगाने के लिए 13.88 करोड़ की अनुदान राशि जारी

**जयपुर**, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2019 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) की स्थापना के लिए 13.88 करोड़ की अनुदान राशि जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले अपशिष्ट का उचित उपचार किया जा सकेगा तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) लगाने पर प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 20 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अधिक से अधिक उद्योगों को अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उक्त योजना लाई गई है।

**राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार शाम प्रताप नगर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में सम्मिलित हुए। समारोह में उपस्थित चिकित्सकों एवं विशिष्ट जनों ने मिश्र से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। राज्यपाल ने उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे।**

**असम विधानसभा की याचिका समिति के सदस्यों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी से निवास स्थान पर शिष्टाचार भेट की। डॉ. जोशी से समिति के सभापति तरोष गेवान समिति के सदस्य नीजानूर रहमान, रूपेश गोवाला, मीहिर कान्तशोर से मुलाकात की। इसके बाद राजस्थान विधानसभा भवन, सदन एवं गैलरियों, राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का भी अवलोकन किया। असम विधान सभा की याचिका समिति के सदस्यों को विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने समिति के सदस्यों को, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया, नियमावली एवं समिति की आन्तरिक कार्य प्रणाली पुस्तिका व साहित्य भेंट किया।**

## 'चिकित्सक संवेदनशीलता के साथ करें मरीजों का इलाज'

**जयपुर**, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता के साथ प्रदेशवासियों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप गांवों-कस्बों तक उत्कृष्ट चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंच रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है।

गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारम्भ की हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि जानकारी के अभाव में कोई इनके लाभ से वंचित न रहे। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के साथ आमजन का फीडबैक लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज स्वास्थ्य सेवाओं में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। आज प्रदेश में एम.आर.आई., सीटी स्केन जैसी महंगी जांचों के साथ-साथ हार्ट, लीवर, बोनमैरो ट्रांसप्लांट जैसा महंगा इलाज निःशुल्क करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों का आह्वान करते हुए कहा कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों का इलाज सेवाभाव एवं संवेदनशीलता के साथ मानवीय आधार पर करें। गहलोत ने निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए भी आग्रह किया।

## अल्प आय वर्ग के लोगों को मिलेंगे रियायती दर पर पट्टे

**जयपुर**, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों में अल्प आय वर्ग के लोगों को भूखण्डों की प्रीमियम दर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, 120 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों की प्रीमियम दर 5 रूपये प्रति वर्गमीटर पर एवं प्रीमियम दर की चार गुना दर पर दस वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा करवाने पर तथा 500 रूपए का भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क जमा करवाने पर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जा सकेगा। इनमें ऐसी कॉलोनियां शामिल हैं जिनके ले-आउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं अथवा सुओ-मोटो सर्वे एवं धारा 90-ए की कार्यवाही कर ले-आउट प्लान/सर्वे प्लान स्वीकृत किए जाने हैं।

## रमेश मीणा ने उड़ीसा में स्वयं सहायता समूहों का काम देखा

**जयपुर**, (का.सं.)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने गुरूवार को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की और वहां ग्रास रूट पर जारी ग्रामीण आजीविका विकास के कार्यों की जानकारी ली।

राजस्थान में राजीवका को एक आन्दोलन का रूप देकर गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लगातार प्रयास कर रहे।

मीना ने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान गुरूवार को उड़ीसा में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया और वहां आजीविका ग्रामीण आजीविका के विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों के संबंध में विशेष चर्चा की। इस दौरान उड़ीसा की आजीविका विकास परिषद से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने उनके नए-नए व्यवसायों के सम्बन्ध में श्री मीना को जानकारी दी।

इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्री मीना ने भी राजस्थान में राजीविका के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किये जा रहे व्यवसाय एवं नवाचारों के अनुभव उनके साथ साझा किए।

उन्होंने स्वयं सहातया समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित एक कैफे में भोजन किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इससे पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी पहुंचने पर स्थानीय निवासियों की ओर से मीना का परंपरागत तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया गया। मंदिर में दर्शन कर मीना ने समस्त देश और प्रदेश में समृद्धि, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रार्थना की।

# मेवात क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार प्रथम प्राथमिकता : जुबैर खान

- सचिवालय में मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए

**जयपुर**, (का.सं.)। मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल के अध्यक्ष जुबैर खान ने कहा है कि मेवात क्षेत्र में मण्डल के माध्यम से प्राथमिकताएं तय कर अधिकाधिक ऐसे काम हाथ में लिए जाएंगे जिससे क्षेत्र में शिक्षा को बढावा मिले, सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार आए और श्मशान एवं कब्रिस्तान जैसी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

खान ने गुरूवार को सचिवालय में मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल की बैठक के दौरान अधिकारियों को इसी भावना के साथ कार्यों की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा की अत्यधिक आवश्कता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नए स्कूल खोलने और उन्हें क्रमोन्नत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन अब उनमें आधारभूत सुविधाओं के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बोर्ड भी ऐसे कार्य हाथ में लेकर स्कूलों के विकास के लिए काम करेगा। साथ ही ऐसे गांव या क्षेत्र जो किसी बाधा के कारण अन्य क्षेत्रों से कटे हुए हैं, उनकी कनेक्टिविटी के कार्य भी चरणबद्ध रूप से स्वीकृत किए जाएं। श्मशान की चारदीवारी, टीनशेड निर्माण और कब्रिस्तान की चारदीवारी के कार्य भी योजना में लिए जाएंगे। साथ ही क्षेत्र के ऐसे काम भी हाथ में लिए जाएंगे जो राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि बोर्ड के माध्यम से गोशालाओं का भी विकास किया जा रहा है। इसमें एक गोशाला अलवर जिले में एवं एक अन्य भरतपुर जिले में विकसित की जा रही है। इसी प्रकार हाट बाजार विकसित किए जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के स्थानीय हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को एक मंच उपलब्ध हो सकेगा एवं मेवात क्षेत्र की गंगा-जमुनी संस्कृति को बढावा मिलेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने भी मेवात क्षेत्र को शिक्षा में समृद्ध बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि गुरूवार की बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना में शिक्षा की प्रथम प्राथमिकता रखी गई है ताकि क्षेत्र और आगे वाली पीढी को शिक्षा में समृद्ध बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत अलवर एवं भरतपुर जिलों में 25 करोड़ की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की जाती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री जाहिदा खान ने भी बैठक में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों एवं शिक्षा एवं कनेक्टिविटी की आवश्यकता के सम्बन्ध में बात रखी। अलवर के रामगढ से विधायक सफिया जुबेर खान ने भी क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी मांग रखी।

विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा ने अधिकारियों से कहा कि बोर्ड से सम्बन्धित पूर्व वर्षों के अप्रारम्भ कार्यों का निरस्तीकरण, राशि के समयोजन एवं अपूर्ण कार्यों की जल्द पूर्णता सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि जल्द ही भरतपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। बैठक में वीडियो कॉर्फ्रेसिंग के माध्यम से अलवर एवं भरतपुर जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिवालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा एवं अन्य हितधारक विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

## वनपाल परीक्षा के लिए मुफ्त मिलेगी यात्रा सुविधा

**जयपुर**, (का.सं.)। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 की पालना के क्रम मे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6 नवम्बर, को आयोजित परीक्षा के परीक्षार्थियों को साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा के आदेश जारी किये गये है।

राजस्थान रोडवेज मुख्यालय से सभी मुख्य प्रबन्धकों को पाबन्द किया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2020, 6 नवम्बर में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को आने व जाने की सुविधा प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त आई.डी. के आधार पर एक दिवस पूर्व एवं परीक्षा के एक दिवस बाद के लिये निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करावें। परीक्षार्थी के गांव व शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने व वापिस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नही होने पर एक से अधिक कनेक्टींग बस का उपयोग कर सकेंगे।

परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग, यात्रा के दौरान मास्क की पालना पूर्णरूप से करनी होगी।

**दीवाली जाते ही सर्दी की दस्तक, लगने लगे रेनबसेरे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने रेनबसेरे लगाने शुरू कर दिए हैं। रामनिवास बाग के पीछे गेट पर तैयार रेनबसेरा।**

# महानरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा

- सौ दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को मिलेगा अतिरिक्त काम
- मास्टर ट्रेनर्स की आमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न

**जयपुर**, (का.सं.)। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन गुरूवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में हुआ।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की सचिव मंजू राजपाल एवं कमिश्नर मनरेगा शिवांगी स्वर्णकार ने योजना का महत्व एवं इसके विविध पक्षों की जानकारी प्रतिभागियों को दी। प्रतिभागियों को बताया गया कि वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा।

दिनभर में विभिन्न सत्रों के दौरान उन्हें योजना के लिए व्यक्तियों की पात्रता, योजना में व्यक्तिगत लाभ एवं सामुहिक लाभ के अनुमत कार्य, राशि की व्यवस्था अन्य योजनाओं से इस योजना के कन्वर्जेंस की स्थिति, योजना मं आवेदन एवं उसकी जांच एवं उसे स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया सहित विभिन्न तकनीकी पक्षों की जानकारी कार्यशाला में दी गई।

योजना में राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से 5 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण उपरान्त 31 अक्टूबर को ये जिला स्तर की कार्यशाला में सभी ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों यथा विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता एवं एमआईएस मैनेजर को प्रशिक्षण देंगे। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 2 नवम्बर को सभी सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारी, जेटीए, को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

## प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे : राजेन्द्र राठौड़

**जयपुर**। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, को प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में गंदगी देखकर शर्मिंदा होना पड़ा वो भी तब जब वह स्वयं अस्पताल में भर्ती थे।

राठौड़ ने कहा कि मरीजों के बाद अब तो खुद मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में व्याप्त गंदगी और अपनी ही सरकार में चरमराई चिकित्सा व्यवस्था की कलई खोल दी है। राज्य के मुखिया का शर्मिंदा होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे है और सरकार के तमाम दावे झूठे हैं।

## रोशन सैनी राष्ट्रीय महासचिव बने

**जयपुर** (कासं)। अखिल भारतीय सैनी माली महासंघ की दिल्ली में आयोजित बैठक में जयपुर के जिला अध्यक्ष रोशन सैनी को महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव मनोनित किया गया है।

# समर्थन मूल्य पर होगी मूंग, उदड़, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद

## किसानों के लिये ऑनलाइन पंजीयन शुरू हुआ

- राजफैड 1 नवम्बर से मूंग, उड़द, सोयाबीन तथा 18 नवम्बर से मूंगफली की करेगा खरीद
- उपज खरीद के लिए केवीएसएस तथा जीएसएस पर बनाए 879 खरीद केन्द्र

**-कार्यालय संवाददाता-**

**जयपुर**। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि प्रदेश मेंं राजफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिये ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर से शुरू हो गया है। 879 खरीद केन्द्रों पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की 1 नवम्बर से तथा 18 नवम्बर से मूंगफली खरीद की जाएगी।

आंजना ने बताया मूंग के लिए 363, उड़द के लिए 166, मूंगफली के 267 तथा सोयबीन के लिए 83 खरीद केन्द्र खोले गए है। जिसमेंसे 419 केन्द्र क्रय-विक्रय सहकारी समितियों पर तथा 460 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाए गए है।

आंजना ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र एवं खरीद केन्द्रों पर प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक की गई है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग का खरीद का लक्ष्य 3 लाख 2 हजार 745 मीट्रिक टन, उडद का 62 हजार 508 मीट्रिक टन, मूंगफली का 4 लाख 65 हजार 565 मीट्रिक टन तथा सोयाबीन का 3 लाख 61 हजार 790 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है। मूंग का समर्थन मूल्य 7755 रूपये, उडद का 6600, मूंगफली का 5850 एवं सोयाबीन का 4300 रूपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू श्रेणी का घोषित किया गया है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि किसान को जनआधार कार्ड नम्बर, खसरा गिरदावरी की प्रति एवं बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड़ करनी होगी। जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करवाया जायेगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि ई-मित्र केन्द्र भी समर्थन मूल्य योजना मे किसानों का पंजीयन पूर्ण सावधानी से करें और तहसील से बाहर पंजीयन नही करें।

उन्होंने बताया कि किसान एक जनआधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेगा। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस तहसील में कृषि भूमि में उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केन्द्र पर उपज बेचान हेतु पंजीकरण करावें। दूसरी तहसील में पंजीकरण मान्य नही होगा।

आंजना ने बताया कि किसान पंजीयन कराते समय यह सुनिश्चित कर ले कि पंजीकृत मोबाईल नम्बर, से जनआधार कार्ड से लिंक हो जिससे समय पर तुलाई दिनांक की सूचना मिल सके। किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दे ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 27 अक्टूबर से हेल्प लाइन नम्बर 1800-180-6001 आरम्भ कर दिया जाएगा।

# रुई के गोदाम में आग से झुलसे मजदूर की मौत

**जयपुर**। सुभाष चौक इलाके में मंगलवार शाम रुई के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। इस दौरान गोदाम में मौजूद एक मजदूर की झुलसने से मौत हो गई। सुभाष चौक पुलिस ने दो दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस ने बुधवार दोपहर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ लापहरवाही के चलते मौत का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि हादसे में महबूब (50) पुत्र भोलू खां निवासी बहीद कॉलोनी गलतागेट की मौत हो गई। पानों का दरिबा सुभाष चौक में अब्दुल बहाव ने मकान में ही रुई गोदाम बना रखा है। रुई गोदाम में महबूब रुई पिनाई का काम करता था। घटनाक्रम के मुताबिक, दीपावली की शाम महबूब गोदाम में काम कर रहा था। शाम करीब 7 बजे पटाखे की चिंगारी से रुई गोदाम में आग लग गई। आग की भीषण लपटे गोदाम से उठने लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

लोगों ने पुलिस को बताया कि गोदाम में महबूब नाम का मजदूर फंसा है। जिसने अंदर से गेट बंद कर रखा है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से गेट खोलकर अंदर फंसे मजदूर महबूब को बाहर निकाला। महबूब आग से जगह-जगह से झुलस गया। पुलिस ने प्राइवेट वाहन से उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने दो दमकलों की मदद से करीब 10 मिनट की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। उधर रुईई गोदाम में झुलसे मजदूर महबूब की बुधवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।